भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *264

जिसका उत्तर 06.08.2026 को दिया जाना है

केन्द्रीय सड़क कोष के अंतर्गत सड़कों का निर्माण

*264. श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को शिरडी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के 8 तालुकों की 18 सड़कों (जिनकी लागत 330 करोड़ रुपए है) को केन्द्रीय सड़क कोष के अंतर्गत शामिल करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इन सड़कों की जर्जर स्थिति और श्रद्धालुओं के समक्ष आ रही कठिनाइयों की जानकारी है;

(ग) इस संबंध में शिरडी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत किए गए लिखित अनुरोधों के संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(घ) क्या सरकार का विचार तीर्थयात्रा और कृषि वस्तुओं की ढुलाई के दृष्टिगत इन 18 सड़कों के महत्व को देखते हुए इन सड़कों को विशेष वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन सड़कों के निर्माण की परियोजनाओं के लिए निविदा प्रक्रिया कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ङ) विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

"केन्द्रीय सड़क कोष के अंतर्गत सड़कों का निर्माण" के संबंध में श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे द्वारा पूछे गए दिनांक 06 अगस्त, 2026 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *264 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ङ) केन्द्रीय सरकार की भूमिका पीएम गति शक्ति की रूपरेखा (फ्रेमवर्क) के भीतर राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र की सड़कों के विकास के लिए राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्राथमिकताकृत परियोजनाओं की सूची को मंजूरी देने तक सीमित है। यह फ्रेमवर्क केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) के अंतर्गत परियोजनाओं की पहचान, स्वीकृति और कार्यान्वयन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में कार्य करता है। सीआरआईएफ के अंतर्गत राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों की संचित राशि और पहले से स्वीकृत कार्यों अर्थात, बैंक ऑफ़ सेंक्शन (बीओएस) की बकाया प्रतिबद्ध देनदारियों के संबंध में राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा प्राथमिकताकृत और प्रस्तुत की गई ऐसी परियोजनाओं की सूची अनुमोदित की जाती है।

शिरडी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के स्थानीय जनप्रतिनिधियों से सीआरआईएफ के तहत शिरडी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 330 करोड़ रुपये की लागत वाली 18 सड़कों के विकास को शामिल करने के लिए प्राप्त लिखित अनुरोध सीआरआईएफ के तहत परियोजनाओं की प्राथमिकताकृत सूची में विचार हेतु महाराष्ट्र राज्य सरकार को अग्रेषित कर दिया गया है। वर्तमान स्थिति के अनुसार, उपरोक्त परियोजनाओं सहित सीआरआईएफ के तहत राज्य सड़क परियोजनाओं की ऐसी कोई प्राथमिकताकृत सूची महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा अनुशंसित नहीं की गई है।

*****